राष्ट्रीय जीडीपी में उप्र ने बढ़ाई चार प्रतिशत भागीदारी : योगी

अनुपूरक बजट पर बोले मुख्यमंत्री, मूल बजट का 20 प्रतिशत हिस्सा विकास कार्यों में हुआ खर्च

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर आक्रामक मुद्रा में जवाब दिया। सपा शासन में प्रदेश की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमें विरासत में जैसा उप्र मिला था और जैसा है, वह सबके सामने है। राष्ट्रीय जीडीपी में उप्र की भागीदारी छह-सात प्रतिशत से बढ़ाकर नौ से 10 प्रतिशत तक पहुंची है। राष्ट्रीय जीडीपी में उप्र की भागीदारी चार प्रतिशत बढ़ गई है। कहा हम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति ... 'मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे, तो दूसरा गढ़े...' से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप बजट का दायरा बढ़ाया। वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्तमान में उप्र का बजट दोगुणा से अधिक है। उप्र रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन चुका है और अपनी ज्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करने में सक्षम हो चुका है। सरकार पावर कारपोरेशन को 46 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में देती है। किसानों को 60 हजार से अधिक सोलर पैनल उपलब्ध कराए गए हैं।

योगी ने विधानसभा में कहा कि उप्र को वन ट्रिलियन डालर इकोनामी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 12 हजार 209.93 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाए हैं। फरवरी माह में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पारित मूल बजट की 44 प्रतिशत धनराशि जारी हो चुकी है और 20 प्रतिशत खर्च की जा चुकी है। राष्ट्रीय जीडीपी में उप्र की भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा, वित्तीय वर्ष 2024-25 का मूल बजट सात लाख 36 हजार 437.71 करोड़ रुपये का था। हमने बिना भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए सरकार की कार्ययोजना को आगे बढ़ाया है। पूंजीगत व्यय दर्शाता है कि बजट की रकम बड़े निर्माण में लग रही है। यह अनुपूरक बजट उप्र में निवेश बढ़ाने वाला है। सर्वांगीण विकास के लिए जो नए मद बनाए गए हैं, उनके लिए इस नए अनुपूरक बजट की आवश्यकता पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा, उप्र देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का माद्दा रखता है। वर्ष 2017 में उप्र की अर्थव्यवस्था देश में छठे-सातवें नंबर पर थी। उप्र के सामने पहचान का संकट था। पर अब धारणा बदल चुकी है। यूपी ने अपनी अर्थव्यवस्था को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना लिया है। सरकार अगले तीन और पांच वर्ष का रोडमैप तैयार कर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य व कौशल विकास में बड़े काम हुए हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। दूसरे राज्यों से कामगार वापस आए हैं और अब प्रदेश में ही काम कर रहे हैं।

गुरुवार को मानसून सत्र के दौरान सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान किसी बात पर हंसते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ●रवनाथ तिवारी

- अगले पांच वर्षों की विकास योजनाओं को लेकर कदम बढ़ा रही सरकार
- वर्ष 2015-16 की तुलना में दोगुणा से अधिक हुआ प्रदेश का बजट

डीबीटी के जरिए भेजे 70 हजार करोड़ :

योगी ने कहा कि 11 विभागों के माध्यम से 196 योजनाओं के लिए 70 हजार करोड़ रुपये का हस्तांतरण डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे गरीबों के खातों में हुआ है।

कर चोरी रोकने को किए कड़े प्रबंध :

योगी ने कहा कि कर चोरी को रोकने के लिए कड़े प्रविधान किए गए हैं। वर्ष 2017 में यूपी का ऋण जमा अनुपात 44 प्रतिशत है, जो अब 60 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं। राजकोषीय जवाबदेही व बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) की अधिकतम सीमा 3.5 प्रतिशत है। जबकि उप्र 2.86 प्रतिशत पर अपने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सफल रहा है।

प्रदेश में बनेंगे चार नए विश्वविद्यालय

योगी ने बताया कि प्रदेश में चार नए विश्वविद्यालय बनेंगे। इनमें मुरादाबाद में गुरु जंभेश्वर के नाम पर विवि बनेगा। देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी के नाम पर, मीरजापुर मंडल में मां विंध्यवासिनी व कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण होगा।

ये भी खास :

- 284 राजकीय इंटर कालेज में प्रयोगशालाओं के लिए 28.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- 1,040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कम्युनिकेशन टेक्नोलाजी लैब की स्थापना के लिए 66 करोड़ रुपये
- हाकी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू के नाम पर बाराबंकी में संग्रहालय बनाएगी सरकार
- कौशल विकास में युवाओं के प्रशिक्षण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रविधान
- 150 आइटीआइ को टाटा कंसल्टेंसी के साथ मिलकर विश्वस्तरीय स्किल डवलपमेंट सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना, जिसमें 23 प्रकार के न्यू एज कोर्स की शुरुआत भी होने जा रही है।